प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

05.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

'' मुख्य समाचार''

- आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संसाधन जुटाना बना चुनौती–विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–हिमकेयर योजना में हुए घोटाले की सी.ए.जी. से जांच करवा रही है सरकार।
- उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा– जलशक्ति विभाग में पैरावर्कर्स को आठ साल में दैनिक भोगी बनाने के लिए बनेंगी नीति।
- धर्मशाला के तपोवन में आयोजित प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सम्पन्न–85 प्रतिशत रही सदन की उत्पादकता।
- शिमला जिला की जुब्बल तहसील के झड़ग गांव में 54 साल बाद शांत महायज्ञ का आयोजन।

कैग रिपोर्ट

प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेल रही हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था दबाव में है और जहां प्राकृतिक आपदाओं से खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं जीएसटी दरों में बदलाव व उत्पादन शुल्क प्राप्तियों में भी कमी से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत एफआरबीएम रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4 दशमलव सात–चार फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में वेतन व पेंशन का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष

वीओ..... आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संसाधन जुटाना अहम चुनौती बना हुआ है। केंद्रीय करों के सहारे ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था चल रही है। प्रदेश के अपने संसाधनों से खजाने में महज 33 फीसदी रकम आ रही है। बाकी 67 फीसदी राशि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी अथवा अनुदानों से हासिल हो रही है। विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में प्रदेश का राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों में प्रस्तावित 10 हजार 3 सौ 37 करोड 97 लाख रुपए के मुकाबले बढ़कर 12 हजार एक सौ 14 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इससे इस वित्त वर्ष में ही राजकोषीय घाटे में एक हजार 7 सौ 76 करोड़ रुपए का और इजाफा होगा। लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटा प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और घाटे को पूरा करने व राजस्व बढ़ाने के उददेश्य से विशेषज्ञों ने प्रदेश में कर व गैर कर राजस्व में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। एफआरबीएम की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में वेतन व पेंशन का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। वेतन पर चालू वित्त वर्ष में 13 हजार 8 सौ 37 करोड 36 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में उपदानों पर एक हजार 4 सौ 20 करोड़ रुपए खर्च होने का बजट अनुमान था, मगर यह खर्च 2 हजार 5 सौ 8 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह उपदान में खर्च पर एक हजार 88 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे और ब्याज पर सरकार इस साल 6 हजार 7 सौ 38 करोड 85 लाख रुपए अधिक खर्च करेगी।

हिमाचल के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं व अनुदान में चालू वित्त वर्ष में एक हजार 6 सौ 62 करोड 73 लाख रूपए का इजाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से वित्तीय वर्ष में मिलने वाली 5 हजार 2 सौ 63 करोड़ के बजट अनुमानों से अधिक है। जाहिर है कि इस साल केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं व अनुदानों से प्रदेश को 6 हजार 9 सौ 25 करोड़ की राशि मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश का राजस्व घाटा भी 7 हजार 4 सौ 34 करोड 93 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कैग रिपोर्ट में एसडीआरएफ के फंड के दुरुपयोग का भी खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकलेखा समिति के कहने तथा कैग द्वारा आपत्ति जताए जाने के बावजूद 2021–22 में

एसडीआरएफ के 22 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि को नियमों के विपरीत खर्च किया गया है। रिपोर्ट में इस तरह के खर्चों पर पूरी तरह से नकेल कसने को कहा गया है।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमकेयर योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार सीएजी से इसकी जांच करवा रही है। इसमें महालेखाकार द्वारा ऑडिट भी शामिल है। विधानसभा में प्रश्नकाल दौरान विधायक विनोद कुमार और त्रिलोक जम्वाल के संयुक्त सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमकेयर योजना के तहत अभी तक निजी अस्पतालों का 2 सौ 11 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है, जबकि एक सौ 10 करोड़ रुपए शेष है और कुल मिलाकर हिमकेयर के तहत 2 सौ 80 करोड़ रुपए का भुगतान करने को है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 2 सौ 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ उतना ही इलाज रोगियों का करेगी, जितना पैसा केंद्र से आएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार भविष्य में आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अब कोई पैसा खर्च नहीं करेगी और आयुष्मान भारत योजना पर प्रदेश सरकार की ओर से खर्च की जाने वाली राशि को हिमकेयर पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र से सिर्फ 43 करोड़ रुपए ही मिले है, जबकि प्रदेश सरकार इस योजना पर एक सौ 10 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना कि इस योजना के तहत भुगतान में कुछ समस्या जरूर आई है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमकेयर योजना के तहत जरूरत पड़ने पर एमएस और प्रिंसिपलों को निर्धारित सीमा से अधिक हिमकेयर कार्ड बनाने को अधिकृत किया जाएगा। इससे पहले, मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत मनरेगा वर्करों को हिमकेयर कार्ड बनाने पर कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन मनरेगा वर्करों के पास हिमकेयर कार्ड नहीं है, उनके कार्ड तुरंत बनाए जाएंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य सरकार जलशक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स को 8 साल में दैनिक भोगी बनाने की नीति लाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में विधायक आरएस बाली द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में यह घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में जल रक्षकों को दैनिक भोगी बनाने के लिए 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह से पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और पैरा मल्टी पर्पस वर्कर के लिए कोई नीति नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में विभाग में कार्यरत इन सभी कर्मचारी वर्गों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करते हुए 8 साल में दैनिक भोगी बनाने की नीति पर विचार करेगी।

सत्र सम्पन्न

प्रदेश विधानसभा का आठ दिवसीय शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में आज सम्पन्न हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्रों में ये सबसे लंबा सत्र रहा। इन आठ बैठकों के साथ ही प्रदेश विधानसभा के कैलेंडर वर्ष में निर्धारित न्यूनत्तम 35 बैठकों का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 34 घंटे चली और सदन की उत्पादक 85 प्रतिशत रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद पहली बार इस साल प्रदेश विधानसभा की 35 बैठकों का लक्ष्य पूरा हुआ।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान 3 सौ 76 तारांकित और एक सौ 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। नियम 61 के तहत दो और नियम 62 के तहत 10 विषयों पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान 6 बिल पेश व पारित किए गए जबकि एक विधेयक को सदन की चयन समिति को विचार के लिए सौंपा गया। शीतकालीन सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मौजूदा सत्र प्रदेश विधानसभा के इतिहास का कांगड़ा में सबसे लंबा शीतकालीन सत्र था। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान खासकर विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा समय मिला।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को सुने बिना कोई भी चर्चा सार्थक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जहां अपनी बात रखने के लिए कई मौके होते हैं वहीं विपक्ष के पास

विधानसभा सत्र ही ऐसा मौका है जहां वह अपना पक्ष खुलकर रख सकता है इसलिए विपक्ष को अधिक समय मिलना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र के दौरान तलखी के कई मौके आए लेकिन सत्र की समाप्ति पर यह तलखी साथ नहीं जानी चाहिए।

महायज्ञ

शिमला जिला की जुब्बल तहसील के झड़ग गांव में 54 साल के लंबे अंतराल के बाद तीन दिवसीय शांत महायज्ञ आज शुरू हुआ। पारंपरिक विधि–विधान के साथ आरंभ हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। नागेश्वर देवता के कारदार ने बताया कि यह महायज्ञ बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ आयोजित किया जा रहा है और इससे इलाके में सुख समृद्धि बनी रहती है।

'' मुख्य समाचार एक बार फिर''

- आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संसाधन जुटाना बना चुनौती–विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–हिमकेयर योजना में हुए घोटाले की सी.ए.जी. से जांच करवा रही है सरकार।
- उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा– जलशक्ति विभाग में पैरावर्कर्स को आठ साल में दैनिक भोगी बनाने के लिए बनेंगी नीति।
- धर्मशाला के तपोवन में आयोजित प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सम्पन्न–85 प्रतिशत रही सदन की उत्पादकता।
- शिमला जिला की जुब्बल तहसील के झड़ग गांव में 54 साल बाद शांत महायज्ञ का आयोजन।